

लॉयल्टी सॉल्यूशंस एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम बनाम। 499

भारतीय संघ और अन्य (जसवंत सिंह, जे.)

समक्ष जसवंत सिंह और संत प्रकाश, जे.

लॉयल्टी सॉल्यूशंस एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम-122003,

हरियाणा-याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय संघ और अन्य प्रतिवादियों

2020 का सी. डब्ल्यू. पी. नंबर 8350

18 फरवरी, 2021

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-रिट याचिका-वित्त अधिनियम, 2019-एस. एस. 123 से 125-माफी योजना-सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019-योजना के तहत ब्याज और जुर्माने की माफी-सी. ई. एस. टी. ए. टी. (प्रक्रिया) नियम, 1982 का नियम 6 ए-कर कानून-सख्त व्याख्या का नियम-अति-तकनीकी दृष्टिकोण-लाभकारी विधान-व्याख्या-तथ्यों पर, सेवा कर की मांग को बढ़ाने के लिए चार कारण-विवरण नोटिस जो 18.04.2018 को सामान्य क्रम में मूल आदेश द्वारा तय करके जारी किए गए -प्रतिवादी ने आंशिक मांग को छोड़ दिया, हालांकि ब्याज के साथ बचे हुए कर की राशि की मांग और लगाए गए जुर्माने की पुष्टि की गई -प्रतिवादी द्वारा अक्टूबर 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए 5 वां कारण-विवरण नोटिस जारी किया गया -याचिकाकर्ता ने क्रम में मूल आदेश के खिलाफ सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राधिकरण में एकल अपील को प्राथमिकता दी - अपील के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता ने सेवा कर का सारा पैसा क्रम में मूल आदेश के अनुसार जमा करवा दिया - प्रतिवादी ने क्रॉस -

अपील दायर की जिसमे आंशिक मांग की पुष्टि हुई - माफ़ी योजना 2019 पेश की गयी - याचिकर्ता ने दो प्राथनाएं ब्याज माफ़ी और योजना के तहत दंड माफ़ी के लिए लगाई - एक आवेदन प्राधिकरण के समक्ष लंबित अपील के सम्बन्ध में था और दूसरा पांचवे कारण बताओ नोटिस के बारे में था - योजना के तहत नामित समिति ने प्राधिकरण के समक्ष दायर अपील के सम्बन्ध में घोषणा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने चार कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में एकल घोषणा दायर की थी, जबकि नियम 3 (2 ) **SVLDR**, 2019 के अनुसार उसे हर कारण बताओ नोटिस के लिए अलग से आवेदन दाखिल करना था - चुनौती दी गयी - 5 वे कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में घोषणा को स्वीकार किया गया - आयोजित **SVLDR** नियमों के नियम 3 (2 ) के तहत एकल लंबित अपील के सम्बन्ध में एक घोषणा का मुद्दा अब एकीकृत नहीं रह गया था - समन्वय पीठ ने 2020 के **CWP** 10804 में इस प्रश्न को निपटाया था और राय दी कि आवेदन को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि चार अलग - अलग दाखिल नहीं की गई -

- समन्वय पीठ के विचार का पालन किया गया और याचिका की अनुमति दी गई-इसके अलावा, प्रतिवादी की याचिका कि सख्त व्याख्या का नियम लागू होगा और कराधान में कोई समानता नहीं थी, भी बनाए रखने योग्य नहीं थी-याचिकाकर्ता ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. (प्रक्रिया) नियम, 1982 के नियम 6 ए की प्रक्रिया के अनुसार सामान्य आदेश के खिलाफ प्राधिकरण के समक्ष एकल अपील दायर

की-नियम एक से अधिक कारण बताएँ नोटिस के संबंध में एकल अपील दायर करने की अनुमति देता है-अपील दायर करना एक महत्वपूर्ण अधिकार है जबकि सर्वक्षमा योजना के तहत घोषणा दायर करना केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता है जो वित्त अधिनियम, 2019 की 123 से 125 एस. एस. में निर्धारित आवश्यक शर्तों का अनुपालन होने पर कायम रखने योग्य है - इन शर्तों का याचिकाकर्ताओं द्वारा पालन किया जाता है, इस प्रकार उन्हें दावा की गई राहत से वंचित नहीं किया जा सकता है-सर्वक्षमा योजना कानून का एक टुकड़ा नहीं है, इसके बजाय, यह संघ के साथ-साथ डीलरों/मूल्यांकनकर्ताओं के लिए लाभकारी कानून का एक टुकड़ा है-इसे मुकदमेबाजी को कम करने के लिए शुरू किया गया था-अधिकारियों का अति-तकनीकी दृष्टिकोण लाभकारी योजना और संसद के जनादेश के इरादे और उद्देश्य के विपरीत है-यह तय कानून है, यदि कोई व्यक्ति एक या दूसरे लाभ के लिए पात्र है, तो उसे प्रक्रियात्मक या तकनीकी आधारों पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए-याचिका की अनुमति है।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि, उपरोक्त निष्कर्षों के पूरक के रूप में, हम यह ध्यान देना उचित पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. (प्रक्रिया) नियम, 1982 के नियम 6 ए को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण के समक्ष एकल अपील दायर की, जिसमें निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित सामान्य आदेश के खिलाफ विभिन्न कारण बताए जाने वाले नोटिस शामिल हैं। 1982 के नियमों का नियम 6 ए निम्नानुसार है:-

“ नियम 6 ए दायर की जाने वाली अपीलों की संख्या।—

कारण दर्शाओ नोटिसों की संख्या के बावजूद, मूल्य सूचियाँ, वर्गीकरण सूचियाँ, प्रवेश के बिल, शिपिंग बिल, धनवापसी के दावे/माँगें, पत्र या घोषणाएँ

निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की गई, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि अपीलकर्ता आदेश या निर्णय के खिलाफ नियम 9 में दी गई प्रतियों की संख्या के साथ नीचे दिए गए प्राधिकारी एक अपील का ज्ञापन दायर करता है।

स्पष्टीकरण— (1) ऐसे मामले में जहां विवादित अपील में आदेश एक से अधिक मूल आदेशों के संदर्भ में पारित किया गया है, नियम 6 के अनुसार जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, दायर अपील के ज्ञापन की संख्या मूल आदेशों की संख्या जितनी होगी जिससे मामला संबंधित है।

(2) यदि एक से अधिक व्यक्तियों के संबंध में कोई विवादित आदेश है, तो प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को एक अलग अपील दायर करने की आवश्यकता होगी (और सामान्य अपील या संयुक्त अपीलों पर विचार नहीं किया जाएगा)।

**[जोर दिया गया]**

(पैरा 9)

आगे उपरोक्त उद्धृत नियम को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि एक आदेश के संबंध में, कारण बताए जाने के नोटिसों की संख्या के बावजूद एकल अपील दायर की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने निर्विवाद रूप से एक से अधिक कारणदर्शक नोटिसों के संबंध में एकल अपील दायर की थी। प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करना एक महत्वपूर्ण अधिकार है जबकि सर्वक्षमा योजना के तहत घोषणा दायर करना केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता है क्योंकि घोषणा बनाए रखने योग्य है यदि पात्रता शर्तों का पालन किया जाता है जो वित्त अधिनियम, 2019 की खंड 123 से 125 के तहत गिने जाते हैं। निस्संदेह, याचिकाकर्ता सभी पात्रता शर्तों का पालन कर

रहे हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को दावा की गई राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 10)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी के वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, हम उनके इस तर्क पर विचार करते हैं कि विधायिका के इरादे में प्रवेश नहीं किया जा सकता है यदि भाषा साफ़ और स्पष्ट है, विशेष रूप से कराधान के मामलों में। विचाराधीन योजना कराधान कानून का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह संघ के साथ-साथ विक्रेताओं/निर्धारिती के लिए लाभकारी कानून का एक हिस्सा है। सरकार को मुकदमेबाजी के बिना राजस्व मिल रहा है और निर्धारिती को आंशिक कर देयता के साथ-साथ ब्याज और जुर्माने से छूट मिल रही है, इस प्रकार दोनों पक्षों के लिए लाभ की स्थिति है। सर्वक्षमा योजना मुकदमेबाजी को कम करने के लिए शुरू की गई थी और ऐसा लगता है कि प्रतिवादी अनावश्यक रूप से मामले को खींच रहा है। अधिकारियों/अधिकारियों का अति तकनीकी दृष्टिकोण लाभकारी योजना के इरादे और उद्देश्य और संसद के जनादेश के विपरीत है। वित्त अधिनियम ने योजना से विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को बाहर रखा है और यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता योग्य व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। कराधान के तहत भी यह तय कानून है कि यदि कोई व्यक्ति एक या दूसरे लाभ के लिए पात्र है, तो उसे प्रक्रियात्मक या तकनीकी आधार पर उक्त लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पात्रता सुनिश्चित करने के लिए शर्तों के सख्त अनुपालन की आवश्यकता है, हालांकि प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। एक या अधिक घोषणाओं को दाखिल करना नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है जबकि पात्रता की शर्तें वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा निर्धारित की गई हैं। अलग से घोषणा दाखिल करना शर्त ही नहीं है बल्कि यह एक तरह की

प्रक्रिया है। एक बार जब कोई निर्धारित वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करता है और एकाधिक के बजाय एकल घोषणा दाखिल करने से राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमें किसी भी शर्त का पालन न करने के आधार पर लाभ से इनकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है जो विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक प्रकृति का है। एल एंड टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बनाम त्रिशूल डेवलपर्स एंड अदर (2020) 10 एस. सी. सी. 659 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले से हमारे निष्कर्ष मजबूत हुए हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी कार्रवाई को केवल एक तुच्छ आपत्ति उठाने पर कानूनी रूप से बुरा नहीं माना जा सकता है, जिसमें खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है, जब तक कि व्यक्ति कोई ठोस पूर्वाग्रह दिखाने में समर्थ न हो। वर्तमान मामले में, राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है या होगा और यदि याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती है, तो अति तकनीकी दृष्टिकोण को अपनाने की अनुमति सर्वक्षमा योजना के उद्देश्य के आलोक में उसके प्रति गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाला जाएगा।

(पैरा 11)

तरुण गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता, द्वारा सहायता प्राप्त

एस/श्री संदीप चिलाना और

तुषार शर्मा, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए (2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8350 में)

एस/श्री निखिल गुप्ता और

ऋषभ सिंगला, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए (2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8755 में)

सुनीश बिंदलिश, अधिवक्ता

प्रतिवादियों के लिए।

**जसवंत सिंह, जे.**

(1) इस सामान्य आदेश के अनुसार, तत्काल दो रिट याचिकाएं 2020 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8350 और 8755, जिसमें समान मुद्दे शामिल हैं, निपटाई जाती हैं। याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल याचिकाओं द्वारा से दिनांकित 24.02.2020 (अनुलग्नक पी -19 2020 की CWP नंबर 8350 में) और 15.01.2020 (अनुलग्नक पी -18 2020 की CWP नंबर 8755 में) के आदेशों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिसके तहत सर्वक्षमा योजना के तहत याचिकाकर्ता (गण) द्वारा दायर घोषणाओं को नामित समिति द्वारा खारिज कर दिया गया है।

(2) सुविधा के लिए, तथ्यों को 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8350 से लिया गया है। यद्यपि विभिन्न अवधियों के लिए आरोपों के एक ही समूह पर प्रतिवादी चार कारणदर्शक नोटिस जारी कर सेवा कर की मांग जो सामान्य आदेश-इन-मूल संख्या 25-28/सी. ओ. एम. एम. आर./पी. के. एल./आर. एस./2018 दिनांक 18.04.2018 (अनुलग्नक पी-7) द्वारा तय की गई थी। प्रतिवादी ने आंशिक मांग को छोड़ दिया, हालांकि ब्याज के साथ कर की शेष राशि की मांग की पुष्टि की और आगे जुर्माना लगाया। प्रतिवादी ने अक्टूबर, 2016 से जून, 2017 की अवधि के लिए दिनांक 27.12.2018 (अनुलग्नक पी-6) का 5 वां कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने सीमा शुल्क और सेवा कर अपील प्रार्थना, चंडीगढ़ (संक्षिप्त में 'प्राधिकरण') के समक्ष सामान्य मूल आदेश दिनांक 18.04.2018 (P-7) के खिलाफ एकल अपील को प्राथमिकता दी, प्राधिकरण के समक्ष अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने सेवा कर की पूरी राशि जमा कर दी, जैसा कि उपरोक्त मूल आदेश द्वारा

पुष्टि की गई है।प्रतिवादी ने उसी मूल आदेश के खिलाफ प्रति अपील दायर की जिसमें आंशिक मांग की पुष्टि की गई थी।

(3) लंबित विवादों के परिसमापन और बकाया कर/बकाया प्राप्त करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा से प्रतिवादी ने 'सबका विश्वास' (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के रूप में सर्वक्षमा योजना शुरू की।याचिकाकर्ता सर्वक्षमा योजना के तहत दो आवेदन दायर कर ब्याज और जुर्माने को माफ करने की मांग की क्योंकि 100% कर की राशि पहले ही भुगतान की जा चुकी थी। प्राधिकरण के समक्ष लंबित अपील के संबंध में 24.12.2019 दिनांकित एक आवेदन दायर किया गया था और दूसरा दिनांक 06.03.2019 दिनांकित 5 वें लंबित कारण दिखाएँ नोटिस के लिए दिनांकित 24.12.2019 को दायर किया गया था।

(4) सर्वक्षमा योजना के तहत गठित नामित समिति ने दिनांक 24.02.2020 (पी-19) के विवादित आदेश के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष लंबित अपील के संबंध में दायर घोषणा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने चार कारण बताएँ नोटिसों के संबंध में एकल घोषणा दायर की है, जबकि याचिकाकर्ता एसवीएलडीआर नियम, 2019 के नियम 3 (2) के संदर्भ में प्रत्येक कारण बताएँ नोटिस के लिए अलग-अलग आवेदन दायर करने के लिए बाध्य था।प्रतिवादी ने 5 वे कारण बताओ नोटिस के संबंध में घोषणा स्वीकार कर ली।

(5) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने चार कारणदर्शक नोटिसों के संबंध में सही तरीके से एक ही आवेदन दायर किया है क्योंकि सी. ई. एस. टी. ए. टी. (प्रक्रिया) नियम, 1982 के नियम 6 ए के अनुसार यदि सामान्य आदेश पारित किया जाता है तो कारण दर्शाएँ नोटिसों की संख्या के बावजूद एक ही अपील बनाए रखी जा सकती है।योजना का उद्देश्य मुकदमेबाजी विचाराधीनता होने को कम



करना और बकाया राशि का भुगतान करना है। योजना के अनुसार, एक घोषणाकर्ता कर की छूट का हकदार है जो 70 प्रतिशत तक बढ़ सकता है यदि कर/शुल्क की राशि रु 50 लाख या उससे कम हो। यदि कोई घोषणाकर्ता कई कारणदर्शक नोटिसों या अपीलों के संबंध में कई घोषणाएं करता है, तो वह कर 50 लाख रूपए के 70 प्रतिशत की छूट का हकदार है, यदि इसमें शामिल राशि 50 लाख रूपए से अधिक है तो प्रतिरक्षा की पात्रता 50 प्रतिशत तक आती है। इस तरह, एक से अधिक कारणदर्शक नोटिसों के लिए एकल आवेदन दायर करने के मामले में, इसमें शामिल राशि को बढ़ाकर 50 लाख रूपये से अधिक किए जाने की सभी संभावनाएं हैं। इस प्रकार एक घोषणाकर्ता कई आवेदन करने की बजाये एकल आवेदन दाखिल करने में लाभार्थी नहीं है।

2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8755 में, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एक कारण दर्शाओ नोटिस में शामिल कर की राशि 50 लाख रूपये से कम थी, इस प्रकार अगर उन्होंने अलग से आवेदन किया होता तो उन्हें 50 प्रतिशत के बजाय 70 प्रतिशत की छूट मिल जाती। योजना का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और बकाया राशि प्राप्त करना है, इस प्रकार सर्वक्षमा योजना कराधान कानून का एक हिस्सा नहीं है, जबकि यह लाभकारी कानून का एक हिस्सा है, इसलिए योजना के इरादे पर विचार किया जाना चाहिए। एस. वी. एल. डी. आर. नियम, 2019 के नियम 3 (2) में कारण बताएँ नोटिस विचाराधीन होने के मामले में अलग से घोषणा दायर करने की आवश्यकता है, जबकि अपील विचाराधीनता होने के मामले में, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आदेश से अपील उत्पन्न होती है और एक आदेश किसी भी संख्या में कारण बताएँ नोटिस पर निर्णय ले सकता है। वर्तमान मामले में, एकल आदेश पारित किया गया था, हालांकि चार संख्याएँ यानी 25-28 आवंटित

की गई थीं, फिर भी मूल क्रम में उद्धृत कारण-विवरण संख्या का कोई विभाजन नहीं है।

(6) प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि भारत में निर्णय सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम एसीआईटी-मनु/आईडी/0462/2016, हेमलता गाग्या बनाम सी. आई.<sup>1</sup> सहित विभिन्न निर्णयों के अनुसार सख्त व्याख्या का नियम लागू होगा और कराधान में कोई समानता नहीं है। प्रतिवादी अधिकारियों को कानून के विपरीत कार्य करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। अधिनियम 3 (2) की भाषा काफी साफ़ और स्पष्ट है, इसलिए विधायिका के इरादे पर गौर करने का कोई सवाल ही नहीं है। वित्त अधिनियम, 2019 की खंड 125 (2) में प्रावधान है कि घोषणा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जाएगी जो निर्धारित की जाए और नियम 3 (2) में प्रत्येक कारण दर्शाओ नोटिस के लिए अलग-अलग घोषणा निर्धारित की गई है, इस प्रकार घोषणा को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

(7) प्रतिद्वंद्वी तर्कों और मामले के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, हम पाते हैं कि इसमें शामिल मुद्दा अब एकीकृत नहीं है। इस न्यायालय की समन्वित पीठ ने 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10804 में हाथ में लिए गए प्रश्न पर विचार किया है और 25.09.2020 दिनांकित आदेश के अनुसार संबंधित पैरा 6 से 14 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-  
“6. तदनुसार, याचिकाकर्ता ने एक आवेदन 30 दिसंबर, 2019 को एस. वी. एल. डी. आर. एस. 1 रूपए 26,68,220.50/- के रूप में इसके 'कर बकाया' और रुपये 6,67,056/- का पूर्व-जमा के रूप में।

7. यह वह आवेदन है जिसे अब इस आधार पर विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता को चार अलग-अलग घोषणाएं/आवेदन दायर करने चाहिए थे।

8. अदालत ने नोट किया कि नियमों के नियम 3 (2) के तहत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक 'मामले' के लिए एक अलग आवेदन दायर किया जाना है। इसके तहत स्पष्टीकरण एक 'मामले' को निम्नानुसार परिभाषित करता है:-

“(क) 30 जून, 2019 तक लंबित इस तरह के नोटिस से उत्पन्न होने वाला कारण दर्शाओ नोटिस या एक या अधिक अपील या

(ख) बकाया राशि; या

(ग) कोई पूछताछ या जांच या लेखा परीक्षा जहां राशि की मात्रा 30 जून, 2019 को या उससे पहले निर्धारित की जाती है; या

(घ) एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

9. इस प्रकार, वर्तमान मामले में यह देखा गया है कि 30 जून, 2019 तक, चार कारण बताओ नोटिस लंबित नहीं थे। वास्तव में, इन पर निर्णय लिया गया था और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा चार कारण बताओ नोटिस में एक समेकित आदेश पारित किया गया था। इसी तरह, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा संयुक्त अपील में एक समेकित आदेश पारित किया गया था। इसके कारण सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष एक अपील दायर की गई है। इसलिए याचिकाकर्ता का यह तर्क देना उचित है कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष एकल लंबित अपील के संबंध में एस. वी. एल. डी. आर. एस. नियमों के नियम 3 (2) के संदर्भ में भी एक घोषणा दायर करने की आवश्यकता है। इसलिए, न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि क्यों एक अति-तकनीकी आधार पर कि चार

अलग-अलग घोषणाएं दायर नहीं की गईं, एसवीएलडीआरएस के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

10. प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ स्थायी वकील श्री सौरभ गोयल, वित्त अधिनियम की खंड 121 (ओ) में 'आदेश' की परिभाषा की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हैं, जो "किसी भी अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत निर्धारण का आदेश है, जो इस तरह के अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत जारी कारण दिखाएं नोटिस के संबंध में पारित किया गया है।"

11. न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अमर प्रताप सिंह की याचिका में योग्यता पाता है कि उपरोक्त परिस्थितियों में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की खंड 13 (2) को लागू किया जा सकता है जिसके संदर्भ में "एकवचन में शब्दों में बहुवचन शामिल होगा, और इसके विपरीत।"

12. किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था कि चार नहीं, बल्कि एक घोषणा 30 दिसंबर, 2019 को दायर की गई थी।

13. इसके अलावा, अदालत ने नोट किया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के इस कथन पर विवाद नहीं किया है कि यदि चार अलग-अलग घोषणाएं दायर की जानी हैं, तो याचिकाकर्ता को केवल रु। 13,34,110/- ही अदा करने हैं, जबकि अब दायर की गई घोषणा के संदर्भ में, याचिकाकर्ता रुपये 26, 68, 220.50/- का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है।

14. उपरोक्त सभी कारणों से, 21 फरवरी, 2020 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। प्रतिवादी को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एस. वी. एल. डी. आर. एस. 1 प्रपत्र में याचिकाकर्ता की घोषणा/आवेदन

पर नए सिरे से निर्णय लेने और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को निर्णय से अवगत कराने का निर्देश जारी किया जाता है।”

(8) प्रतिवादी के वकील का सामना किए जाने पर वर्तमान मामले के तथ्यों को इस न्यायालय के उपरोक्त फैसले से अलग नहीं कर सके, हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि विभाग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर करने की प्रक्रिया में है।केवल एस. एल. पी. दाखिल करने या एस. एल. पी. दाखिल करने का इरादा मामले को लंबित रखने या किसी भी राय को उसी संख्या की समन्वय पीठ की राय से अलग रखने का कोई आधार नहीं है, इस प्रकार हम सम्मानपूर्वक उपरोक्त निर्णय का पालन करते हैं और वर्तमान याचिका को अनुमति देना उचित पाते हैं।

(9) उपरोक्त निष्कर्षों के पूरक के रूप में, हम इस बात पर ध्यान देना उचित पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. (प्रक्रिया) नियम, 1982 के नियम 6 ए को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण के समक्ष एकल अपील दायर की, जिसमें निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित सामान्य आदेश के खिलाफ विभिन्न कारण बताए जाने वाले नोटिस शामिल हैं। 1982 के नियमों का नियम 6 ए निम्नानुसार है:-

“ नियम 6 ए दायर की जाने वाली अपीलों की संख्या। —

कारण दर्शाओ नोटिसों की संख्या के बावजूद, मूल्य सूचियाँ, वर्गीकरण सूचियाँ, प्रवेश के बिल, शिपिंग बिल, धनवापसी के दावे/माँगें, पत्र या घोषणाएँ जिस निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की गई है, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि अपीलकर्ता आदेश या निर्णय के खिलाफ एक अपील का ज्ञापन दायर करे नीचे दिए गए प्राधिकारी की प्रतियों की संख्या के साथ, जैसा कि नियम 9 में दिया गया है।

स्पष्टीकरण — (1) एक ऐसे मामले में जहां आक्षेपित आदेश-इन-अपील एक से अधिक मूल आदेशों के संदर्भ में आदेश पारित किया गया है, नियम 6 के अनुसार दायर किया गया अपील ज्ञापन मूल आदेशों की संख्या जितना होगा, जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है।

(2) यदि एक से अधिक व्यक्तियों के संबंध में कोई विवादित आदेश है, तो प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को एक अलग अपील दायर करने की आवश्यकता होगी (और सामान्य अपील या संयुक्त अपीलों पर विचार नहीं किया जाएगा)।

### [जोर दिया गया]

(10) उपरोक्त उद्धृत नियम को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि एक आदेश के संबंध में, कारण बताए जाने के नोटिसों की संख्या के बावजूद एकल अपील दायर की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने निर्विवाद रूप से एक से अधिक कारणदर्शक नोटिसों के संबंध में एकल अपील दायर की थी। प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करना एक महत्वपूर्ण अधिकार है जबकि सर्वक्षमा योजना के तहत घोषणा दायर करना केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता है क्योंकि घोषणा बनाए रखने योग्य है यदि पात्रता शर्तों का पालन किया जाता है जो वित्त अधिनियम, 2019 की खंड 123 से 125 के तहत गिने जाते हैं। निस्संदेह, याचिकाकर्ता सभी पात्रता शर्तों का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को दावा की गई राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(11) प्रतिवादी के वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, हम उनके इस तर्क पर विचार करते हैं कि विधायिका के इरादे में प्रवेश नहीं किया जा सकता है यदि भाषा साफ और स्पष्ट है, विशेष रूप से कराधान मामलों में। विचाराधीन योजना कराधान कानून का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह संघ के साथ-साथ विक्रेताओं/निर्धारिती के लिए लाभकारी कानून का एक

हिस्सा है। सरकार को मुकदमेबाजी के बिना राजस्व मिल रहा है और निर्धारिती को आंशिक कर देयता के साथ-साथ ब्याज और जुर्माने से छूट मिल रही है, इस प्रकार दोनों पक्षों के लिए लाभ की स्थिति है। सर्वक्षमा योजना मुकदमेबाजी को कम करने के लिए शुरू की गई थी और ऐसा लगता है कि प्रतिवादी अनावश्यक रूप से मामले को खींच रहा है। अधिकारियों/प्राधिकारियों का अति तकनीकी दृष्टिकोण लाभकारी योजना के इरादे और उद्देश्य और संसद के जनादेश के विपरीत है। वित्त अधिनियम योजना से विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को बाहर रखा गया है और यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता योग्य व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। कराधान के तहत भी यह तय कानून है कि यदि कोई व्यक्ति एक या दूसरे लाभ के लिए पात्र है, तो उसे प्रक्रियात्मक या तकनीकी आधार पर उक्त लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पात्रता सुनिश्चित करने के लिए शर्तों के सख्त अनुपालन की आवश्यकता है, हालांकि प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। एक या अधिक घोषणाओं को दाखिल करना नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है जबकि पात्रता की शर्तें वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा निर्धारित की गई हैं। अलग से घोषणा दाखिल करना शर्त नहीं है जबकि यह एक तरह की प्रक्रिया है। एक बार जब कोई निर्धारिती वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करता है और एकाधिक के बजाय एकल घोषणा दाखिल करने से राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमें किसी भी शर्त का पालन न करने के आधार पर लाभ से इनकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है जो विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक प्रकृति का है। एल एंड टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बनाम त्रिशूल डेवलपर्स और अन्य<sup>2</sup> में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले से हमारे निष्कर्ष मजबूत हुए हैं, जिसमें यह माना गया है कि केवल एक तुच्छ आपत्ति उठाने पर एक कार्रवाई को

कानून में बुरा नहीं माना जा सकता है, जिसमें खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है, जब तक कि व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह दिखाने में समर्थ न हो। वर्तमान मामले में, राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है या होगा और यदि याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती है, तो अति तकनीकी दृष्टिकोण को अपनाने की अनुमति सर्वक्षमा योजना के उद्देश्य के आलोक में उसके प्रति गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाला जाएगा।

(12) हमारे उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार अनुमति दी जाती है।

विवादित आदेश दिनांकित 24.02.2020 (अनुलग्नक पी -19 2020 की CWP नंबर 8350 में) और दिनांकित 15.01.2020 (2020 की CWP नंबर 8755) एतद्वारा निरस्त किया जाता है और प्रतिवादी को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं द्वारा अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक - कुलभूषण